

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड  
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून- 248001  
Email ID- ceo\_uttaranchal@eci.gov.in फोन न० (0135) - 2713760, 2713551  
फैक्स न० (0135) - 2713724

संख्या: 544 /XXV-12(1-5)/2008 देहरादून: दिनांक 10 अप्रैल, 2018.  
सेवा में,

श्री जीवन सिंह,  
निवासी आरोग्य मेडिकल स्टोर अस्पताल,  
तिराहा, दुग बाजार, बागेश्वर।

विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना के संबंध में।

उपरोक्त विषयक अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी उत्तराखण्ड शासन अनुभाग-7 के पत्र संख्या- 67/XXVII(7)48(46)/2018 दिनांक 06 अप्रैल, 2018 जो आपको सम्बोधित एवं इस कार्यालय को पृष्ठांकित है, का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के क्रम में सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत बिन्दु संख्या-02 एवं बिन्दु संख्या- 03 में चाही गयी वांछित सूचना निम्नानुसार प्रेषित है।

बिन्दु संख्या-02	दिनांक 04 जनवरी, 2017 से दिनांक 15 मार्च, 2017 तक निर्वाचन संबंधी आचार संहिता लागू थी।
बिन्दु संख्या-03	नहीं

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैं:-

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं  
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड  
04-सुभाष रोड़ सचिवालय परिसर, देहरादून।

भवदीय,

B. S. Rawat  
(बी०एस०रावत)

अनुभाग अधिकारी एवं  
लोक सूचना अधिकारी

उत्तराखण्ड शासन  
वित्त(वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7  
संख्या: /XXVII(7)48(46)/2018  
देहरादून: दिनांक 06 अप्रैल, 2018

कार्यालय सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
पत्र प्राप्ति का दिनांक- 6/4/2018  
रजिस्टर क्रमांक- 239 पत्रावली संख्या-

श्री जीवन सिंह,  
निवासी आरोग्य मेडिकल स्टोर अस्पताल,  
तिराहा, दुग बाजार बागेश्वर।

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु अपने पत्र दिनांक 24.03.2018, जो इस कार्यालय को दिनांक 03.04.2018 को प्राप्त हैं, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. आवेदन के बिन्दु संख्या-01 से 07 तक के सम्बन्ध में सूचना निम्नवत् उपलब्ध कराई जा रही है:-

क0 सं0	आवेदन पत्र में वांछित सूचना के सम्बन्ध में	उपलब्ध कराई जाने वाली सूचना/अभिलेख
1.	राज्य सरकार से सरकारी सेवकों के लिए संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-11 दिनांक 17.02.2017 कौन सा विधान सभा सत्र में पास हुआ और कौन सेक्रेटरी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की ?	प्रकरण विधान सभा में प्रस्तुत नहीं हुआ है। अतः सूचना धारित नहीं है।
2.	उत्तराखण्ड विधान सभा चुनाव, 2017 आचार संहिता कब से कब तक लागू थी ?	लोक सूचना अधिकारी, निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-6(3) के अन्तर्गत अन्तरित।
3.	क्या आचार संहिता के दौरान शासनादेश पास हो सकते हैं ?	लोक सूचना अधिकारी, निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-6(3) के अन्तर्गत अन्तरित।
4.	उत्तराखण्ड विधान सभा चुनाव, 2017 आचार संहिता के दौरान कितने शासनादेश पास हुए और इसमें से कितने शासनादेश लागू किये गये और कितने शासनादेश को निरस्त किया गया ?	सूचना विभिन्न विभागों से सम्बन्धित होनी प्रतीत हो रही है। कृपया सम्बन्धित विभागों के लोक सूचना अधिकारियों से सूचना प्राप्त करना चाहें।
5.	सरकारी सेवकों के लिए संशोधित सुनिश्चित प्रोन्नयन योजना 10+20+30 योजना लागू शासनादेश संख्या-11 दिनांक 17.02.2017 को पास कराते समय क्या माननीय राज्यपाल महोदय से अनुमति ली गयी ?	सूचना प्रश्नोत्तरी के रूप में है। सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना उचित प्रतीत होता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नियम 2(च) व 2(झ) में अभिलेख के रूप में धारित सूचना ही दिये जाने की व्यवस्था विद्यमान है।
6.	राज्य सरकार सरकारी सेवकों के लिए संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना 10+20+30 योजना लागू शासनादेश संख्या-11 दिनांक 17.02.2017 आचार संहिता के दौरान किस नियम के तहत पारित किया गया ?	सूचना प्रश्नोत्तरी के रूप में है। सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना उचित प्रतीत होता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नियम 2(च) व 2(झ) में अभिलेख के रूप में धारित सूचना ही दिये जाने की व्यवस्था विद्यमान है।
7.	उत्तराखण्ड सरकार के पास ऐसे कौन सी परेशानी थी जो आचार संहिता के दौरान राज्य सरकारी सेवकों के लिए संशोधित सुनिश्चित प्रोन्नयन योजना 10+20 +30 योजना लागू किया गया ?	सूचना प्रश्नोत्तरी के रूप में है। सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना उचित प्रतीत होता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नियम 2(च) व 2(झ) में अभिलेख के रूप में धारित सूचना ही दिये जाने की व्यवस्था विद्यमान है।

3. यदि आप उक्त सूचना से सन्तुष्ट नहीं हो तो निम्नवत् पते पर प्रथम अपीलीय अधिकारी को निर्धारित समायान्तर्गत अपील कर सकते हैं।

अरुणेंद्र सिंह चौहान,  
अपर सचिव/प्रथम अपीलीय अधिकारी,  
उत्तराखण्ड शासन, तृतीय तल, कक्ष संख्या-317,  
योजना भवन, सचिवालय, देहरादून।

(सुरेन्द्र सिंह नेगी)  
अनुभाग अधिकारी/  
लोक सूचना अधिकारी।

संख्या- 67/XXVII(7)48(46)/2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. लोक सूचना अधिकारी, निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत अन्तरित श्री जीवन सिंह का पत्र दिनांक 24.03.2018 के बिन्दु-2 व 3 की सूचना अपने स्तर से देने का कष्ट करें।
2. वित्त अधिकारी, सचिवालय प्रशासन, लेखा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन को रू0 50/- का पोस्टल ऑर्डर संख्या-90G 504067 राजकोष में जमा करने हेतु प्रेषित।

(सुरेन्द्र सिंह नेगी)  
अनुभाग अधिकारी/  
लोक सूचना अधिकारी।

सं-र-

1000000 (7)/48/46/2018

सूचना का अधिकार प्राप्त हेतु आवेदन-पत्र :

1. आवेदक का नाम

जीवन सिंह ।

2. पिता का नाम

श्री प्रताप सिंह ।

3. संपर्क का पूरा पता-

निवासी आरोग्य मेडिकल स्टोर अस्पताल  
तिराहा, दुग बाजार बागेश्वर ।

4. इच्छित सूचना का स्पष्ट विवरण-

1. राज्य सरकार से सरकारी सेवकों के लिए  
संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना  
लागू किये जाने के संबंध में शासनादेश सं-  
11 दिनांक 17.2.2017 कोन सा विधेयन  
सभा सत्र में पास हुआ और कोन सेक्टो ने  
रिपोर्ट प्रस्तुत की ?

2. उत्तराखण्ड विधान सभा चुनाव 2017  
आचार संहिता कब से कब तक लागू थी ?  
3. क्या आचार संहिता के दौरान शासनादेश  
पास हो सकते हैं ?

4. उत्तराखण्ड विधान सभा चुनाव 2017  
आचार संहिता के दौरान कितने  
शासनादेश पास हुए और इसमें से कितने  
शासनादेश लागू किये गये और कितने  
शासनादेश को निरस्त किया गया ?

5. सरकारी सेवकों के लिए संशोधित सुनिश्चित  
प्रोन्नयन योजना 10+20+30 योजना

लागू शासनादेश सं-11 दि-17-2-2017 को  
पास कराते समय क्या माननीय राज्यपाल  
महोदय से अनुमति ली गयी ?

6. राज्य सरकार सरकारी सेवकों के लिए  
संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना  
10+20+30 योजना लागू शासनादेश सं-11  
17-2-2017 आचार संहिता के दौरान

किस नियम के तहत पारित किया गया ?

7. उत्तराखण्ड सरकार के पास ऐसे कोन से  
परेशानी थी जो आचार संहिता के दौरान  
राज्य सरकार सेवकों के लिए संशोधित  
सुनिश्चित प्रोन्नयन योजना 10+20+30  
योजना लागू किया गया ?

सूचनाधिकारी वित्त सचिव उत्तराखण्ड

सरकार वित्त विभाग अनुभाग-7

10/-रु0 का नॉन जूडिशियल स्टॉप सिलान  
तथा 50/-का पोस्टल आर्डर ।

5. संबंधित विभाग का नाम

6. आवेदन शुल्क जमा करने का विवरण-

7. गरौबी रेखा से नोचे जीवन यापन करने का

8. आवेदन-पत्र जमा करने का दिनांक

24.03.2018.

9. आवेदक के हस्ताक्षर-जीवन

4 जनवरी / 15 मार्च 2017 तः

SB

7E

A. Anusman

03.4.2018

Prakash Chandra JOSTI  
सुराभ्य विवेकता  
ID No. UK1239804  
Rs.

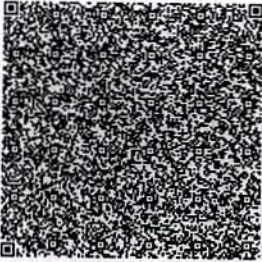


सत्यमेव जयते

**INDIA NON JUDICIAL**  
**Government of Uttarakhand**

**e-Stamp**

Certificate No. : IN-UK58982030735889Q  
Certificate Issued Date : 24-Mar-2018 11:45 AM  
Account Reference : NONACC (SV)/ uk1239804/ BAGESHWAR/ UK-BG  
Unique Doc. Reference : SUBIN-UKUK123980418912390691831Q  
Purchased by : JEEWAN SINGH SON PRATAP SINGH KATHYATBARA BGR  
Description of Document : Article 4 Affidavit  
Property Description : NA  
Consideration Price (Rs.) : 0  
(Zero)  
First Party : JEEWAN SINGH SON PRATAP SINGH KATHYATBARA BGR  
Second Party : NA  
Stamp Duty Paid By : JEEWAN SINGH SON PRATAP SINGH KATHYATBARA BGR  
Stamp Duty Amount(Rs.) : 10  
(Ten only)



-----Please write or type below this line-----

केवल

सूचना

के

अधिकार

के प्रयोजनार्थः:--- १०---

**Statutory Alert:**

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority